(SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (c) In order to implement the obligations contained in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), which is a part of the World Trade Organisation (WTO) Agreement, India has time till January 1, 2000 to implement the obligations contained in the Agreement and further time till January 1, 2005 to introduce product patent protection to areas of technologies not protected so far. However, the member countries of WTO, who have opted to avail of the latter period, were required to comply with the obligations contained in Articles 70.8 and 70.9 of the TRIPs Agreement with effect from January 1, 1995.

In order to comply with these obligations which came into force from January 01,1995 and also to comply with. WTO rulings in the Indo-US Dispute on Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical products, Government is exploring different options and strategies.

Cent-per-cent FDI in cigerette Industry

819. SHRI RAJUBHAIU A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI AKHILESH DAS:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have dcided to allow 100 per cent foreign direct investment (FDI) in cigaretts industry;. and

(b) if so, how far it is a in consonance with Government's declared National agenda of Swadeshi spirit prohibiting FDI in non-essential consumer products in economy and ban on advertising tobacco products?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) The existing guidelines for consideration of Foreign Direct Investment proposals by FIPB do not stipulate any ceiling on the extent of foreign equity participation in consumer non-durables sector including cigarettes.

The National agenda for Governance refers to encouraging FDI in core sectors so as to usefully supplement national efforts and discouraging FDI in non-priority areas. As per para 7(e) of the guidelines for the consideration of FDI proposals by FIPB, items that have a direct or backward linkages with agro-business and/or farm sector are considered for foreign direct investment on priority.

सरकारी क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाइयां

820. श्री कपिल सिब्बल:
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1997-98 में सरकारी क्षेत्र में 253 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत थीं;

(ख) यदि नहीं, तो उनकी वास्तविक संख्या का अनुमान क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन संस्थाओं द्वारा गत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान लाभांश अर्जित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना-कितना लाभांश अर्जित किया गया;

(ङ) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संस्थाओं में कितनी-कितनी धन राशि का निवेश किया गया; और

(च) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान इस धनराशि पर कितना-कितना ब्याज अदा किया गया?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (च) 31-3-1997 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार उक्त अवधि तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 236 उपक्रम प्रचालनरत थे। वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान केन्द्रीय

सरकारी क्षेत्र के क्रमशः 78 एवं 80 उपक्रमों ने लाभांश का भुगतान किया। अन्य जानकारी इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

	1995-96	1996-97
भुगतान किए गए लाभांश की राशि	2205	3080
पूंजीनिवेश	100917	112321
भुगतान किया गया ब्याज	6204	7903

औद्योगिक मंदी से प्रभावित हुआ सेवा क्षेत्र

821. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजकल भारतीय उद्योग भीषण मंदी के दौर से गुजर रहा है और कई उद्योग और कारखाने या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) क्या इस औद्योगिक मंदी के कारण सेवा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है और उद्योग की तरह इस क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर कम हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न उद्योगों और विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है; और

(घ) सरकार द्वारा उद्योग और सेवा क्षेत्र की उबारने हेतु और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान कुल औद्योगिक विकास क्रमशः 5.6 प्रतिशत तथा 6.6 प्रतिशत था। चालू वर्ष अप्रैल-सितम्बर, 1998 के दौरान विकास की दर पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.0 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत है। किंतु, वाणिज्यिक एककों की संख्या में वृद्धि हुई है। रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अनुसार सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्थापनाओं की संख्या, जो 31 मार्च, 1996 को 2,71,466 थी, 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 2,77,553 हो गई है। विकास आयुक्त, लघु उद्योग से उपलब्ध सूचना के अनुसार लघु क्षेत्र में भी एककों की संख्या 1996-97 के 28.57 लाख से बढ़कर 1997-98 में 30.40 लाख एकक हो गई है।

(ख) और (ग) विभिन्न उद्योगों तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार तथा प्रतिशत परिवर्तन निम्नानुसार है:—

रोजगार (लाख में, 31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं)

उद्योग/सेवाएं	1994	1995	1996
विनिर्माण	64.14	66.21 (3.2)	66.58 (0.6)
विद्युत, गैस तथा जल	9.78	10.07 (2.9)	9.86 (-2.1)
निर्माण	12.18	12.18 (—)	12.06 (-1.0)
थोक तथा खुदरा व्यापार और भोजनालय तथा होटल	4.62	4.76 (1.0)	4.81 (1.0)
परिवहन, भंडारण तथा संचार	31.40	31.57 (0.5)	29.96 (-5.1)
वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यापार सेवाएं	15.55	16.56 (6.5)	16.15 (2.5)
सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं	110.63	112.95 (2.1)	112.01 (-0.8)